Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the *'Committee on Publication Ethics'*

Online ISSN:2584-184X

Research Article

आधुनिकीकरण और ग्रामीण आर्थिक संरचना: कृषि पद्धतियों एवं आय स्रोतों में परिवर्तन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. गुन्जन त्रिपाठी *

सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग आदर्श कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जियापुर, बरुआ-जलांकी, टाण्डा, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश (संबद्ध: डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, उत्तर प्रदेश)

Corresponding Author: * डॉ. गुन्जन त्रिपाठी

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18780515

सारांश

आधुनिकीकरण एक गतिशील सामाजिक प्रक्रिया है जिसके प्रभाव से ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना में व्यापक परिवर्तनों को देखा जा सकता है। परंपरागत रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित रही है, किंतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास, बाजार विस्तार, संचार साधनों की उपलब्धता तथा सरकारी योजनाओं के कारण कृषि पद्धतियों और आय स्रोतों में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पद्धतियों में हुए परिवर्तनों तथा आय स्रोतों के विविधीकरण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। इस शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों में चयनित ग्रामीण परिवारों से साक्षात्कार एवं प्रश्नावली के माध्यम से तथ्य संकलित किए गए, जबकि द्वितीयक आंकड़े पुस्तकों, शोध पत्रों तथा सरकारी रिपोर्टों से प्राप्त किए गए। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि परंपरागत कृषि पद्धतियों के स्थान पर आधुनिक बीज, उर्वरक, सिंचाई साधन तथा मशीनों का प्रयोग बढ़ा है। साथ ही ग्रामीण परिवारों की आय अब केवल कृषि तक सीमित न रहकर मजदूरी, लघु व्यवसाय, सेवा एवं प्रवासन जैसे विविध स्रोतों पर निर्भर होती जा रही है। यह परिवर्तन न केवल आर्थिक संरचना को प्रभावित कर रहा है, बल्कि सामाजिक संबंधों, जीवन स्तर, शिक्षा तथा ग्रामीण जीवन शैली में भी परिवर्तन ला रहा है। अतः आधुनिकीकरण ग्रामीण समाज में बहुआयामी परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में उभर रहा है।

Manuscript Information

- **ISSN No:** 2584-184X
- **Received:** 02-01-2026
- **Accepted:** 24-02-2026
- **Published:** 26-02-2026
- **MRR:**4(2); 2026: 401-407
- **©2026, All Rights Reserved**
- **Plagiarism Checked:** Yes
- **Peer Review Process:** Yes

How to Cite this Article

डॉ. गुन्जन त्रिपाठी . आधुनिकीकरण और ग्रामीण आर्थिक संरचना: कृषि पद्धतियों एवं आय स्रोतों में परिवर्तन का समाजशास्त्रीय विश्लेषण . इंडियन जर्नल ऑफ मॉडर्न रिसर्च रिव्यू. 2026;4(2):401-407.

Access this Article Online

www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: आधुनिकीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि पद्धतियाँ, आय स्रोत, सामाजिक परिवर्तन

© 2026 डॉ. गुन्जन त्रिपाठी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

प्रस्तावना

आधुनिकीकरण आधुनिक समाज के निर्माण की एक निरंतर एवं बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचनाओं में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया केवल तकनीकी प्रगति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक संस्थाओं, मूल्य प्रणाली, उत्पादन संबंधों तथा जीवन शैली को भी प्रभावित करती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से आधुनिकीकरण को पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज की ओर संक्रमण की प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसमें तर्कसंगतता, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा शिक्षा का विस्तार प्रमुख भूमिका निभाते हैं। आधुनिकीकरण के संदर्भ में योगेन्द्र सिंह ने भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता के अंतर्संबंधों का विश्लेषण करते हुए यह प्रतिपादित किया कि भारतीय आधुनिकीकरण एक रेखिक प्रक्रिया न होकर परंपरागत संरचनाओं के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होता है।[1]

भारतीय ग्रामीण समाज ऐतिहासिक रूप से कृषि पर आधारित रहा है। भूमि स्वामित्व, श्रम विभाजन तथा पारंपरिक उत्पादन पद्धतियाँ न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला रही हैं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा, वर्ग संरचना और जातिगत संबंधों को भी निर्धारित करती रही हैं।[2] कृषि यहाँ केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक पहचान और सामुदायिक जीवन का केंद्र रही है। किंतु स्वतंत्रता के पश्चात विशेषकर हरित क्रांति, तकनीकी नवाचार, सिंचाई विस्तार, बाजारों के प्रसार तथा राज्य की विकासोन्मुख नीतियों के परिणामस्वरूप ग्रामीण आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं।[3] आधुनिक बीज, रासायनिक उर्वरक, कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि उत्पादों का व्यावसायीकरण ग्रामीण उत्पादन प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं, जिससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ कृषि का बाजारोन्मुखीकरण भी बढ़ा है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण परिवारों की आय संरचना में भी उल्लेखनीय विविधता आई है। जहाँ पूर्व में अधिकांश परिवार कृषि पर निर्भर थे, वहीं वर्तमान में मजदूरी, लघु उद्योग, स्वरोजगार, सरकारी एवं निजी सेवा तथा प्रवासन से प्राप्त आय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पूरक स्रोत बन गए हैं। यह आय विविधीकरण आर्थिक जोखिम को कम करने के साथ-साथ सामाजिक गतिशीलता को भी प्रोत्साहित करता है। परिणामस्वरूप ग्रामीण समाज में वर्ग संरचना, उपभोग प्रवृत्तियों, शिक्षा के स्तर तथा जीवन शैली में परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है।

हालाँकि आधुनिकीकरण की यह प्रक्रिया ग्रामीण समाज में अवसरों और चुनौतियों दोनों को जन्म देती है। एक ओर उत्पादन में वृद्धि, आय के नए अवसर और जीवन स्तर में सुधार दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक असमानता, संसाधनों का असमान वितरण तथा पारंपरिक सामुदायिक संबंधों में परिवर्तन जैसी समस्याएँ भी उभरती हैं। अतः ग्रामीण आर्थिक संरचना में कृषि पद्धतियों और आय स्रोतों में हुए परिवर्तनों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण आवश्यक हो जाता है, जिससे यह समझा जा सके कि आधुनिकीकरण ग्रामीण सामाजिक ताने-बाने को किस प्रकार पुनर्संरचित कर रहा है। प्रस्तुत शोध-पत्र इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण के प्रभावों तथा उनके सामाजिक निहितार्थों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

साहित्य समीक्षा

रजक (2025) ने बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण कृषि परिवारों में आय और पेशागत विविधीकरण का अध्ययन किया। इस शोध में मिश्रित अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया गया, जिसमें सर्वेक्षण और साक्षात्कार दोनों को शामिल किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण परिवार अब केवल कृषि पर निर्भर न रहकर गैरकृषि गतिविधियों, मजदूरी तथा छोटे व्यवसायों की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही भूमि स्वामित्व, जाति और सामाजिक स्थिति आज भी रोजगार के अवसरों को प्रभावित करते हैं। शोध यह भी दर्शाता है कि आधुनिकीकरण और बाजार के विस्तार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक बहुआयामी बनाया है, किंतु इसके प्रभाव विभिन्न सामाजिक वर्गों पर समान नहीं हैं।[4]

कुमार (2025) ने ग्रामीण भारत में कृषि संबंधों, वर्ग संरचना तथा श्रम संबंधों में आए परिवर्तनों का विश्लेषण किया। उनके अध्ययन में पाया गया कि कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण, उन्नत तकनीकों का प्रयोग, बाजारोन्मुख खेती, प्रवासन तथा रोजगार के विविधीकरण ने पारंपरिक कृषि व्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। विशेष रूप से जाति आधारित श्रम विभाजन और पारंपरिक उत्पादन संबंधों में परिवर्तन आया है, जिससे ग्रामीण सामाजिक संरचना में नए आर्थिक संबंध विकसित हुए हैं। शोध यह भी दर्शाता है कि हरित क्रांति और आर्थिक उदारीकरण के पश्चात कृषि का व्यावसायीकरण बढ़ा, जिसके कारण बड़े एवं संसाधनसम्पन्न किसानों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ प्राप्त हुआ, जबकि छोटे एवं सीमांत किसान आर्थिक असुरक्षा का सामना करते रहे। यह अध्ययन ग्रामीण आर्थिक संरचना में आधुनिकीकरण के असमान प्रभावों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।[5]

एलिस (2008) द्वारा ग्रामीण आजीविका विविधीकरण पर विकास संबंधी अध्ययन कार्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन्होंने ग्रामीण परिवारों द्वारा कृषि के अतिरिक्त आय स्रोत अपनाने को आर्थिक जोखिम से निपटने की रणनीति के रूप में व्याख्यायित किया है। उनके अनुसार कृषि आय की अनिश्चितता, बाजार विस्तार, तकनीकी परिवर्तन और रोजगार अवसरों की उपलब्धता ग्रामीण परिवारों को गैर-कृषि गतिविधियों की ओर प्रेरित करती है। भारत सहित विकासशील देशों में यह प्रवृत्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुआयामी बनाते हुए वर्ग संरचना, उपभोग पैटर्न और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित कर रही है। आजीविका विविधीकरण से एक ओर आय स्थिरता और जीवन स्तर में सुधार होता है, वहीं दूसरी ओर संसाधनों और अवसरों की असमान उपलब्धता के कारण सामाजिक विषमताएँ भी बनी रहती हैं। इस प्रकार, ऐसे अध्ययन आधुनिकीकरण और ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन के संबंध को समझने के लिए सैद्धांतिक आधार प्रदान करते हैं।[6]

जोधका (2017) ने अपने अध्ययन में भारतीय ग्रामीण समाज में गैर-कृषि क्षेत्र के विस्तार का विश्लेषण प्रमुखता से किया है। उनके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा, बाजार संपर्क, अवसंरचना विकास और शहरीकरण के प्रभाव से ग्रामीण आबादी कृषि के अतिरिक्त रोजगारों की ओर अग्रसर हो रही है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सेवा, व्यापार, निर्माण और लघु उद्योगों का महत्व बढ़ा है। गैर-कृषि कार्यों के विस्तार ने सामाजिक गतिशीलता और आय अवसरों को बढ़ाया, परंतु जाति और वर्ग आधारित असमानताएँ अभी भी ग्रामीण जीवन को प्रभावित करती हैं। जोधका का अध्ययन दर्शाता है कि

© 2026 डॉ. गुन्जन त्रिपाठी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

आधुनिकीकरण केवल तकनीकी या आर्थिक परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों, शक्ति संरचना और ग्रामीण पहचान में भी बदलाव लाता है। इस प्रकार गैर-कृषि अर्थव्यवस्था का विकास ग्रामीण परिवर्तन की व्यापक प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है।[7]

थापा और मिश्रा (2022) के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासन और मौसमी रोजगार पर किए गए अध्ययन महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उनके अनुसार कृषि संकट, सीमित भूमि, बेरोजगारी और आय की अनिश्चितता ग्रामीण श्रमिकों को शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास के लिए प्रेरित करती है। प्रवासन से प्राप्त प्रेषण ग्रामीण परिवारों की आय संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिससे उपभोग स्तर, शिक्षा निवेश और जीवन शैली में परिवर्तन देखा जा रहा है। हालांकि प्रवासन से आर्थिक अवसर बढ़ते हैं, परंतु इससे पारिवारिक संबंधों, सामुदायिक सहभागिता और ग्रामीण श्रम संरचना पर भी प्रभाव पड़ता है। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि प्रवासन ग्रामीण आर्थिक संरचना में आय विविधीकरण का प्रमुख साधन बन गया है और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में ग्रामीण-शहरी अंतर्संबंधों को मजबूत करता है।[8]

आधुनिकीकरण, कृषि परिवर्तन और ग्रामीण आर्थिक संरचना का अंतरसंबंध

आधुनिकीकरण और कृषि परिवर्तन के अंतर्संबंध को केवल उत्पादकता वृद्धि तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह ग्रामीण आर्थिक संरचना में संस्थागत पुनर्गठन, जोखिम प्रबंधन और बाजार एकीकरण की नई प्रक्रियाओं को जन्म देता है। समकालीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि अब एक स्वतंत्र गतिविधि न रहकर मूल्य श्रृंखला आधारित प्रणाली का हिस्सा बनती जा रही है, जहाँ उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और विपणन के बीच परस्पर निर्भरता बढ़ी है। टेरी मार्सडेन के अनुसार कृषि का यह "री-टेरिटोरियलाइजेशन" ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों और वैश्विक बाजारों के बीच नए आर्थिक संबंध स्थापित करता है, जिससे ग्रामीण आर्थिक संरचना बहुस्तरीय हो जाती है।[9]

कृषि आधुनिकीकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में जोखिम और अनिश्चितता के प्रबंधन के नए तंत्र विकसित किए हैं। फसल बीमा, संविदा कृषि तथा डिजिटल बाजार प्लेटफॉर्म जैसी व्यवस्थाएँ किसानों को बाजार उतार-चढ़ाव से आंशिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। अशोक गुलाटी का तर्क है कि संस्थागत नवाचार, कृषि विपणन सुधार तथा मूल्य श्रृंखला एकीकरण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करते हैं, किंतु छोटे किसानों की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित न होने पर ये सुधार असमानता को भी बढ़ा सकते हैं।[10]

इसके अतिरिक्त, कृषि परिवर्तन ने ग्रामीण श्रम संरचना में "हाइब्रिड आजीविका" की प्रवृत्ति को जन्म दिया है, जहाँ परिवार कृषि, सेवाओं और सूक्ष्म उद्यमों को मिलाकर आय अर्जित करते हैं। सतुरनीनो जुन एम. बोरास जूनियर के अनुसार यह प्रवृत्ति ग्रामीण पूंजीवाद के नए रूप को दर्शाती है, जिसमें भूमि, श्रम और पूंजी के पारंपरिक संबंध पुनर्गठित होते हैं।[11] दूसरी ओर, मोबाइल बैंकिंग, ई-नाम जैसे प्लेटफॉर्म और डेटा आधारित कृषि सेवाएँ ग्रामीण आर्थिक संरचना को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ रही हैं। इस प्रकार आधुनिकीकरण, कृषि परिवर्तन और ग्रामीण आर्थिक संरचना का संबंध अब तकनीकी नवाचार, संस्थागत व्यवस्थाओं और वैश्विक-स्थानीय आर्थिक अंतःक्रियाओं के समेकित रूप में उभरता है, जो ग्रामीण विकास के नए प्रतिमान को रेखांकित करता है।

शोध उदेश्य

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पद्धतियों में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
- ग्रामीण परिवारों की आय संरचना में आए विविधीकरण का अध्ययन करना।
- आधुनिकीकरण के प्रभाव से ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक संबंधों में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
- कृषि पद्धतियों और आय विविधीकरण के सामाजिक निहितार्थों का परीक्षण करना।
- ग्रामीण आर्थिक संरचना में आधुनिकीकरण के अवसरों और चुनौतियों का मूल्यांकन करना।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में मिश्रित अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। वर्णनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से कृषि पद्धतियों तथा आय स्रोतों में हुए परिवर्तनों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जबकि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण द्वारा इन परिवर्तनों के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों का परीक्षण किया गया है। इस पद्धति के अंतर्गत मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया गया, जिससे अध्ययन अधिक व्यापक, विश्वसनीय तथा व्याख्यात्मक बन सके।

अध्ययन क्षेत्र एवं नमूना चयन

प्रस्तुत अध्ययन हेतु उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जनपद की अकबरपुर तहसील का चयन उद्देश्यपरक नमूना विधि के आधार पर किया गया है। चयनित तहसील के अंतर्गत तीन गाँवों का चयन यादृच्छिक नमूना विधि द्वारा किया गया है। प्रत्येक गाँव से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 50 ग्रामीण परिवारों को अध्ययन में शामिल किया गया, जिससे कृषि, श्रम तथा आय विविधीकरण की वास्तविक स्थिति को समग्र रूप से समझा जा सके। नमूना चयन की प्रक्रिया में भूमि स्वामित्व, जाति, व्यवसाय तथा आय स्तर जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया, ताकि ग्रामीण आर्थिक संरचना का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। अध्ययन में चयनित प्रत्येक परिवार से एक वयस्क सदस्य को उत्तरदाता के रूप में चयनित किया गया है, जो परिवार की सामाजिक-आर्थिक एवं आजीविका संबंधी गतिविधियों से भली-भाँति परिचित था। जहाँ संभव हुआ, वहाँ परिवार के मुखिया को उत्तरदाता बनाया गया, अन्यथा परिवार के प्रमुख निर्णयकर्ता से प्राप्त जानकारी को संकलित किया गया है। इस प्रकार कुल 150 उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अध्ययन का विश्लेषण किया गया है।

प्रदत्त संकलन विधि

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के द्वारा प्रदत्त का संकलन किया गया है। प्राथमिक विधि में साक्षात्कार तथा अनुसूची, जिसमें खुले एवं बंद दोनों प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया है, के द्वारा चयनित ग्रामीण परिवारों से कृषि तकनीकों, आय स्रोतों और सामाजिक परिवर्तनों से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई। वहीं

© 2026 डॉ. गुन्जन त्रिपाठी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकों, शोध पत्रों, रिपोर्टों, सरकारी प्रकाशनों तथा विभिन्न संस्थागत रिपोर्टों से प्राप्त सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है।

प्रदत्त विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में संकलित प्रदत्तों का विश्लेषण सांख्यिकीय एवं वर्णनात्मक विधियों के माध्यम से किया गया है। प्राथमिक प्रदत्तों को वर्गीकृत कर सारणियों के रूप में प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिशत पद्धति के आधार पर उनका विश्लेषण किया गया। विश्लेषण की प्रक्रिया में उत्तरदाताओं के सामाजिक-आर्थिक परिचय, कृषि पद्धतियों में परिवर्तन तथा आय स्रोतों के विविधीकरण से संबंधित तथ्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत कर उनके समाजशास्त्रीय निहितार्थों की व्याख्या की गई है।

उत्तरदाताओं का सामाजिक-आर्थिक परिचय

सारणी 1: उत्तरदाताओं की आयु संरचना (N=150)

आयु-वर्ग	संख्या	प्रतिशत
18–30 वर्ष	32	21.33
31–40 वर्ष	41	27.33
41–50 वर्ष	38	25.33
50 वर्ष से अधिक	39	26.00
कुल	**150**	**100**

टिप्पणी: गोलाईकरण (Rounding) के कारण कुल 100 प्रतिशत किया गया है।

सारणी 1 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में मध्य आयु वर्ग (31–50 वर्ष) के उत्तरदाताओं का प्रभुत्व है। यह वर्ग ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों, विशेषकर कृषि एवं पूरक रोजगारों में सक्रिय भूमिका निभाता है। युवा वर्ग की उपस्थिति नई तकनीकों एवं वैकल्पिक रोजगारों के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाती है, जबकि अधिक आयु वर्ग पारंपरिक कृषि ज्ञान एवं सामाजिक निर्णयों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह आयु संरचना ग्रामीण समाज में परंपरा एवं आधुनिकता के सहअस्तित्व को दर्शाती है।

सारणी 2: उत्तरदाताओं का लिंग वितरण (N=150)

लिंग	संख्या	प्रतिशत
पुरुष	102	68.00
महिला	48	32.00
कुल	**150**	**100**

सारणी 2 के अनुसार पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या अधिक है, जो ग्रामीण समाज में आर्थिक निर्णयकर्ता के रूप में उनकी पारंपरिक भूमिका को दर्शाती है। वहीं महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी यह संकेत देती है कि कृषि, स्वयं सहायता समूहों तथा लघु उद्यमों में उनकी सक्रियता बढ़ रही है। यह प्रवृत्ति ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक योगदान एवं निर्णय प्रक्रिया में धीरे-धीरे बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करती है।

सारणी 3: उत्तरदाताओं की जातिगत संरचना (N=150)

जाति वर्ग	संख्या	प्रतिशत
सामान्य वर्ग	30	20.00
अन्य पिछड़ा वर्ग	78	52.00
अनुसूचित जाति	42	28.00
अनुसूचित जनजाति	0	0.00
कुल	**150**	**100**

सारणी 3 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सर्वाधिक 52 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, जो ग्रामीण सामाजिक संरचना में उनकी प्रमुख उपस्थिति को दर्शाता है। अनुसूचित जाति के 28 प्रतिशत उत्तरदाता पाए गए, जो ग्रामीण श्रम एवं कृषि आधारित गतिविधियों में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी को इंगित करता है। सामान्य वर्ग के उत्तरदाता 20 प्रतिशत हैं, जो अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के उत्तरदाता नहीं पाए गए, अतः इस श्रेणी का प्रतिशत शून्य है।

सारणी 4: उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति (N=150)

शिक्षा स्तर	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	29	19.33
प्राथमिक	46	30.77
माध्यमिक	39	26.00
उच्च माध्यमिक	23	15.33
स्नातक एवं अधिक	13	8.77
कुल	**150**	**100**

सारणी 4 के अनुसार अधिकांश उत्तरदाता प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर से संबंधित हैं, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार के बावजूद उच्च शिक्षा तक सीमित पहुँच को दर्शाती है। साथ ही साक्षरता में वृद्धि आधुनिक कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं तथा गैर-कृषि रोजगारों को अपनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। अतः शिक्षा ग्रामीण आर्थिक संरचना में परिवर्तन एवं सामाजिक गतिशीलता का महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व के रूप में उभरती है।

सारणी 5: भूमि स्वामित्व के आधार का वितरण (N=150)

भूमि स्वामित्व	संख्या	प्रतिशत
भूमिहीन	34	22.67
सीमांत किसान	52	34.67
छोटे किसान	39	26.00
मध्यम किसान	18	12.00
बड़े किसान	7	4.66
कुल	**150**	**100**

सारणी 5 से ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र में छोटे एवं सीमांत कृषकों का प्रभुत्व है, जबकि भूमिहीन एवं बड़े कृषकों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। अध्ययन में मध्यम कृषकों की उपस्थिति भी पाई गई है, किंतु उनका प्रतिशत सीमित है। यह स्थिति भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक विषमता को दर्शाती है। जहाँ सीमित भूमि संसाधन कृषि आय को प्रभावित करते हैं, वहीं भूमिहीन उत्तरदाताओं की उपस्थिति मजदूरी एवं गैर-कृषि कार्यों पर निर्भरता को इंगित करती

© 2026 डॉ. गुन्जन त्रिपाठी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

है। भूमि स्वामित्व की यह असमानता ग्रामीण आर्थिक अवसरों, आय स्तर तथा सामाजिक प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है।

सारणी 6: व्यवसाय संरचना का वितरण (N=150)

व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
कृषि	61	40.7
कृषि मजदूरी	36	24.0
लघु व्यवसाय	21	14.0
सेवा	17	11.3
प्रवासन/अन्य	15	10.0
कुल	**150**	**100**

सारणी 6 के अनुसार अधिकांश उत्तरदाता कृषि एवं कृषि मजदूरी से जुड़े हैं, जबकि कुछ उत्तरदाता लघु व्यवसाय, सेवा तथा प्रवासन आधारित कार्यों में संलग्न पाए गए। यह प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों में आय विविधीकरण एवं गैर-कृषि गतिविधियों के विस्तार को दर्शाती है। व्यवसाय संरचना में यह परिवर्तन आधुनिकीकरण, बाजार संपर्क तथा अवसंरचना विकास के प्रभाव को स्पष्ट करता है। साथ ही यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पारंपरिक कृषि आधारित स्वरूप से बहुआयामी आर्थिक संरचना की ओर संक्रमण का संकेत देता है।

सारणी 7: उत्तरदाताओं का आय स्तरानुसार वितरण (N = 150)

आय स्तर (मासिक)	संख्या	प्रतिशत
₹5,000 तक	36	24.00
₹5,001 से 10,000	49	32.67
₹10,001 से 15,000	34	22.67
₹15,001 से 20,000	18	12.00
₹20,000 से अधिक	13	8.66
कुल	**150**	**100**

सारणी 7 से ज्ञात होता है कि 24.00 प्रतिशत उत्तरदाता ₹5,000 तक के आय वर्ग में आते हैं, जो निम्न आय स्थिति को दर्शाता है। 32.67 प्रतिशत उत्तरदाता ₹5,001 से 10,000 आय वर्ग में पाए गए, जो अध्ययन क्षेत्र में निम्न-मध्यम आय वर्ग की प्रधानता को इंगित करता है। ₹10,001 से 15,000 आय वर्ग में 22.67 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं। वहीं ₹15,001 से 20,000 आय वर्ग में 12.00 प्रतिशत उत्तरदाता पाए गए। उच्च आय वर्ग ₹20,000 से अधिक में केवल 8.66 प्रतिशत उत्तरदाता सम्मिलित हैं। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र में निम्न एवं निम्न-मध्यम आय वर्ग की प्रमुखता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण उद्देश्य आधारित विश्लेषण

सारणी 8: कृषि पद्धतियों में परिवर्तन का विवरण

कृषि परिवर्तन	संख्या	प्रतिशत
उन्नत बीज का प्रयोग	92	61.33
रासायनिक उर्वरक	105	70.00
सिंचाई साधनों का विस्तार	88	58.67
कृषि यंत्रीकरण	76	50.67
परंपरागत पद्धति	32	21.33

टिप्पणी: प्रतिशत कुल उत्तरदाताओं (N = 150) के आधार पर है, उत्तर एकाधिक हैं।

सारणी 8 से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश उत्तरदाता रासायनिक उर्वरक 70 प्रतिशत तथा उन्नत बीज 61.33 प्रतिशत का प्रयोग कर रहे हैं, जो कृषि आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। सिंचाई साधनों का विस्तार 58.67 प्रतिशत एवं कृषि यंत्रीकरण 50.67 प्रतिशत भी उल्लेखनीय स्तर पर अपनाए गए हैं। इसके विपरीत परंपरागत पद्धतियों का उपयोग अपेक्षाकृत कम 21.33 प्रतिशत पाया गया। चूँकि उत्तर एकाधिक थे, अतः कुल प्रतिशत 100 से अधिक है।

सारणी 9: ग्रामीण परिवारों की आय संरचना के विविधीकरण का विवरण

आय स्रोत	संख्या	प्रतिशत
कृषि आय	118	78.67
मजदूरी/दैनिक काम	92	61.33
स्वरोजगार/लघु व्यवसाय	55	36.67
सरकारी/निजी सेवा	27	18.00
प्रवासन से प्राप्त आय	38	25.33

टिप्पणी: प्रतिशत कुल उत्तरदाताओं (N = 150) के आधार पर है, उत्तर एकाधिक हैं।

सारणी 9 से स्पष्ट है कि अधिकांश परिवारों की आय कृषि 78.67 प्रतिशत पर निर्भर है। मजदूरी/दैनिक काम 61.33 प्रतिशत और स्वरोजगार 36.67 प्रतिशत भी महत्वपूर्ण आय स्रोत हैं। सरकारी एवं निजी सेवा 18 प्रतिशत तथा प्रवासन से प्राप्त आय 25.33 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पूरक आय स्रोत हैं। यह विविधीकरण स्पष्ट करता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अब केवल कृषि पर निर्भर नहीं है, बल्कि बहुआयामी बन चुकी है, जो आर्थिक जोखिम प्रबंधन और जीवन स्तर सुधार में सहायक है। चूँकि उत्तर एकाधिक थे, अतः कुल प्रतिशत 100 से अधिक है।

सारणी 10: ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक संबंधों में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण

परिवर्तन का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
संयुक्त परिवार से एकल परिवार की प्रवृत्ति	64	42.67
जाति आधारित पेशों में कमी	71	47.33
शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि	102	68.00
महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि	59	39.33
सामुदायिक सहयोग में कमी	46	30.67

टिप्पणी: प्रतिशत कुल उत्तरदाताओं (N = 150) के आधार पर है, उत्तर एकाधिक हैं।

सारणी 10 से स्पष्ट है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि 68 प्रतिशत ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख संकेतक है। जाति आधारित पेशों में कमी 47.33 प्रतिशत तथा संयुक्त परिवार से एकल परिवार की प्रवृत्ति 42.67 प्रतिशत सामाजिक संरचना में परिवर्तन को दर्शाती है। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी 39.33 प्रतिशत में वृद्धि भी आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण प्रभाव है। साथ ही, सामुदायिक सहयोग में कमी 30.67 प्रतिशत यह इंगित करती है कि आधुनिकीकरण के प्रभाव से पारंपरिक सामूहिकता एवं पारस्परिक सहयोग की भावना कुछ हद तक कमजोर हुई है। यह समग्र रूप से दर्शाता है कि ग्रामीण समाज पारंपरिक संबंधों से आधुनिक, अधिक गतिशील तथा व्यक्तिवादी संरचना की ओर अग्रसर है। चूँकि उत्तर एकाधिक थे, अतः कुल प्रतिशत 100 से अधिक है।

© 2026 डॉ. गुन्जन त्रिपाठी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

सारणी 11: कृषि पद्धतियों और आय विविधीकरण के सामाजिक निहितार्थों का परीक्षण

सामाजिक प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
जीवन स्तर में सुधार	96	64.00
उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि	82	54.67
सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि	74	49.33
पारंपरिक मूल्यों में कमी	51	34.00
आर्थिक असमानता में वृद्धि	43	28.67

टिप्पणी: प्रतिशत कुल उत्तरदाताओं (N = 150) के आधार पर है, उत्तर एकाधिक हैं।

सारणी 11 से स्पष्ट होता है कि कृषि आधुनिकीकरण एवं आय विविधीकरण ने ग्रामीण समाज पर व्यापक सामाजिक प्रभाव डाले हैं। सर्वाधिक 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जीवन स्तर में सुधार को स्वीकार किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि बढ़ी हुई आय एवं उत्पादन ने आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उपभोग सुविधाओं तक पहुँच को सुदृढ़ किया है। उपभोग प्रवृत्ति में 54.67 प्रतिशत वृद्धि इसी परिवर्तन का परिणाम है, जो ग्रामीण परिवारों के बाजारोन्मुखी व्यवहार को दर्शाती है। सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि 49.33 प्रतिशत यह इंगित करती है कि आय के विविध स्रोतों ने व्यक्तियों को पारंपरिक पेशागत सीमाओं से बाहर निकलने तथा शिक्षा एवं रोजगार के नए अवसर अपनाने में सहायता प्रदान की है। इसके विपरीत, 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा पारंपरिक मूल्यों में कमी का उल्लेख यह दर्शाता है कि आर्थिक परिवर्तन के साथ सामुदायिकता, परंपरागत पेशागत पहचान तथा सांस्कृतिक निरंतरता पर आंशिक प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार, 28.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आर्थिक असमानता में वृद्धि को रेखांकित किया, जो यह संकेत देता है कि आधुनिकीकरण के लाभ सभी वर्गों में समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कृषि आधुनिकीकरण एवं आय विविधीकरण ग्रामीण समाज में एक ओर जीवन स्तर सुधार और गतिशीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मूल्य परिवर्तन और असमानता जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न कर रहे हैं। चूँकि उत्तर एकाधिक थे, अतः कुल प्रतिशत 100 से अधिक है।

सारणी 12: ग्रामीण आर्थिक संरचना में आधुनिकीकरण के अवसरों और चुनौतियों का मूल्यांकन

पक्ष	संख्या	प्रतिशत
रोजगार के नए अवसर	88	58.67
बाजार तक बेहतर पहुँच	79	52.67
तकनीकी प्रशिक्षण की कमी	61	40.67
लागत में वृद्धि	84	56.00
प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव	47	31.33

टिप्पणी: प्रतिशत कुल उत्तरदाताओं (N = 150) के आधार पर है, उत्तर एकाधिक हैं।

सारणी 12 से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण आर्थिक संरचना में आधुनिकीकरण ने अवसरों और चुनौतियों दोनों को जन्म दिया है। सर्वाधिक 58.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने रोजगार के नए अवसरों की उपलब्धता को स्वीकार किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि कृषि के साथ-साथ गैर-कृषि गतिविधियाँ, लघु उद्यम तथा सेवा क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। इसी प्रकार, 52.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बाजार तक बेहतर पहुँच का उल्लेख यह दर्शाता है कि परिवहन, संचार तथा डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने किसानों और ग्रामीण उत्पादकों को व्यापक बाजार से जोड़ने में सहायक भूमिका निभाई है। दूसरी ओर, चुनौतियों के रूप में 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने उत्पादन लागत में वृद्धि को प्रमुख समस्या बताया, जो उन्नत बीज, उर्वरक, मशीनरी तथा सिंचाई साधनों पर बढ़ती निर्भरता का परिणाम है। साथ ही 40.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने तकनीकी प्रशिक्षण की कमी को रेखांकित किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिकीकरण के लाभों का प्रभावी उपयोग करने हेतु कौशल विकास एवं विस्तार सेवाओं की आवश्यकता बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, 31.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव का उल्लेख यह इंगित करता है कि गहन कृषि एवं तकनीकी प्रयोग के कारण जल, भूमि तथा पर्यावरणीय संतुलन पर प्रभाव पड़ रहा है। अतः समग्र रूप से कहा जा सकता है कि ग्रामीण आर्थिक संरचना परिवर्तन के संक्रमणकाल से गुजर रही है, जहाँ आधुनिकीकरण एक ओर रोजगार एवं बाजार अवसरों को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी ओर लागत, कौशल एवं पर्यावरणीय चुनौतियाँ नीति-निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण आर्थिक संरचना वर्तमान में संक्रमणकाल से गुजर रही है, जहाँ परंपरागत कृषि आधारित व्यवस्था धीरे-धीरे बहुआयामी एवं बाजारोन्मुखी स्वरूप ग्रहण कर रही है। उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से यह तथ्य सामने आया कि मध्य आयु वर्ग ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख क्रियाशील घटक है, जबकि युवा वर्ग तकनीकी नवाचार एवं वैकल्पिक रोजगारों की ओर अग्रसर है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लैंगिक भूमिकाओं का पुनर्संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। भूमि स्वामित्व की संरचना में छोटे एवं सीमांत कृषकों का प्रभुत्व भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक वास्तविकता को दर्शाता है, जिससे आय स्तर, उत्पादन क्षमता एवं सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती है। व्यवसाय एवं आय संरचना के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि कृषि अभी भी प्रमुख आय स्रोत है, किंतु मजदूरी, स्वरोजगार, प्रवासन एवं सेवा क्षेत्र के विस्तार ने आय विविधीकरण को बढ़ावा दिया है। यह प्रवृत्ति ग्रामीण परिवारों को आर्थिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने तथा जीवन स्तर सुधार में सहायक सिद्ध हो रही है। कृषि आधुनिकीकरण के संदर्भ में उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई एवं यंत्रीकरण के बढ़ते उपयोग ने उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि की संभावनाएँ उत्पन्न की हैं। इसके परिणामस्वरूप जीवन स्तर, उपभोग प्रवृत्ति एवं सामाजिक गतिशीलता में सुधार देखा गया। साथ ही शिक्षा के प्रसार, जाति आधारित पेशों में कमी, तथा एकल परिवार की प्रवृत्ति सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में उभरे हैं। हालाँकि अध्ययन यह भी दर्शाता है कि आधुनिकीकरण के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं। उत्पादन लागत में वृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, तथा प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ता दबाव ग्रामीण विकास की प्रमुख चुनौतियाँ हैं। पारंपरिक मूल्यों एवं सामुदायिक सहयोग में कमी भी सामाजिक परिवर्तन के दुष्परिणामों के रूप में सामने आई है। अतः समग्र रूप से कहा जा सकता है कि कृषि आधुनिकीकरण एवं आय विविधीकरण ग्रामीण समाज में आर्थिक उन्नति और सामाजिक गतिशीलता को प्रोत्साहित कर रहे हैं, परंतु

© 2026 डॉ. गुन्जन त्रिपाठी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

इसके साथ असमानता, लागत एवं पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं।

सुझाव

उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आय अस्थिरता को कम करने तथा सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु बहुआयामी रणनीतियों की आवश्यकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

- **कृषि तकनीकों का समावेशी प्रसार:** छोटे एवं सीमांत किसानों तक उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएँ तथा कृषि यंत्रीकरण को अनुदान एवं सहकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ताकि आधुनिकीकरण के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित हो सके।
- **कौशल विकास एवं तकनीकी प्रशिक्षण:** ग्रामीण किसानों एवं श्रमिकों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं, डिजिटल कृषि, प्रसंस्करण एवं लघु उद्यमों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना आवश्यक है, जिससे तकनीकी ज्ञान की कमी को दूर किया जा सके।
- **आय विविधीकरण को प्रोत्साहन** लघु उद्योग, पशुपालन, हस्तशिल्प, ग्रामीण पर्यटन तथा स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा देकर ग्रामीण परिवारों के लिए वैकल्पिक आय स्रोत विकसित किए जाने चाहिए, जिससे कृषि पर निर्भरता कम हो और आय स्थिरता बढ़े।
- **महिला आर्थिक सशक्तिकरण** स्वयं सहायता समूहों, माइक्रोफाइनेंस तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, जिससे पारिवारिक आय और सामाजिक सशक्तिकरण दोनों में वृद्धि हो सके।
- **बाजार संपर्क एवं अवसंरचना विकास** ग्रामीण सड़कों, भंडारण, परिवहन तथा डिजिटल बाजार प्लेटफॉर्म के विस्तार से किसानों को बेहतर मूल्य एवं विपणन अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिससे ग्रामीण उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।
- **सामाजिक असमानता में कमी हेतु नीतिगत हस्तक्षेप** भूमिहीन एवं कमजोर वर्गों के लिए लक्षित रोजगार योजनाएँ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा संस्थागत ऋण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि आधुनिकीकरण के असमान प्रभावों को कम किया जा सके।

संदर्भ सूची

1. Singh Y. Modernisation of Indian tradition. New Delhi: Thomson Press Limited; 1973.
2. Desai AR. Rural sociology in India. Bombay: Popular Prakashan; 1969.
3. Frankel FR. India's green revolution: Economic gains and political costs. Princeton (NJ): Princeton University Press; 1971.
4. Rajak D. Pattern of occupational diversification among rural agricultural households: A field view. Artha J Soc Sci. 2025;24(1):1–30. doi:10.12724/ajss.72.1.
5. Kumar P, Kumar A. Changing agrarian social relations in contemporary rural India. Int J Interdiscip Cult Stud. 2025;20(1):209–218. doi:10.18848/hgrban52.
6. Ellis F. The determinants of rural livelihood diversification in developing countries. J Agric Econ. 2000;51(2):289–302. doi:10.1111/j.1477-9552.2000.tb01229.x.
7. Jodhka SS, Kumar A. Non-farm economy in Madhubani, Bihar: Social dynamics and exclusionary rural transformations. Econ Polit Wkly. 2017;52(25–26):14–24. Available from: http://www.jstor.org/stable/26696036
8. Thapa R, Mishra DK. Agrarian distress and seasonal out-migration: Insights from a field survey in North Bengal. Sociol Bull. 2022;71(3):396–420. doi:10.1177/00380229221094776.
9. Marsden T. New rural territories: Regulating the differentiated rural spaces. J Rural Stud. 1998;14(1):107–117. doi:10.1016/S0743-0167(97)00041-7.
10. Gulati A. Agriculture: A push for pulses. India Today. 2024 Aug 18. Available from: https://www.indiatoday.in/magazine/cover-story/story/20240826-agriculture-ashok-gulati-a-push-for-pulses-2583201-2024-08-18
11. Borras SM Jr. Agrarian change and peasant studies: Changes, continuities and challenges—an introduction. J Peasant Stud. 2009;36(1):5–31. doi:10.1080/03066150902820297.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

डॉ. गुन्जन त्रिपाठी समाजशास्त्र की विदुषी एवं सहायक प्राध्यापक हैं। वह आदर्श कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जियापुर (बरुआ-जलांकी), टाण्डा, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, जो डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से संबद्ध है। उन्होंने समाजशास्त्र विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी- नेट) उत्तीर्ण की है तथा अपनी पीएच.डी. डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से पूर्ण की है। शिक्षण, शोध एवं छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक मार्गदर्शन में उनकी विशेष रुचि है।

© 2026 डॉ. गुन्जन त्रिपाठी. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC ND).https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/